[श्री धर्मवीर]

टेशन को खत्म किया जाए और वे प्रबन्ध को अपने हाथ में ले लें।

माननीय सदस्य ने जनपथ, गोविन्द-पुरी, एन० डी० एम० सी० और जहांगीर-पुरी में हुई दुर्घटनाओं का जिक्र किया है। ठेकेदारों को नियमों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है। बिल्डिग और कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करने वाले मजदूरों की सेफ्टी के लिए हम एक कंट्रेक्ट वर्कर्ज एक्ट बहुत जल्दी इस सदन में ला रहे हैं, जिसमें इस बारे में सभी प्रावधान होंगे। फिलहाल हमने 4 तारीख को सार्वजनिक संस्थानों को सुरक्षा नियमों का पालन करने के सम्बन्ध में इंस्ट्रक्शन्ज और गाइडलाइन्ज दी हैं।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं। कि हमारी तरफ से कार्यवाही की जा रही है। श्री मिश्र की रिपोर्ट के बारे में बार-बार चर्चा की गई है। हमने चाहा था कि वह रिपोर्ट हमें मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति एक कमिश्नर के रूप में की है। हमें बताया गया है that the case being *sub judice*, the Supreme Court being the custodian of the report, even the contents of the report cannot be used for any purpose except on the direction of the court as and when received.

हम इस रिपोर्ट से पीछा नहीं छुड़ा रहे हैं। जब हमें कोई जानकारी मिलती है, तो हम बंधुओं मजदूरों की सुरक्षा, मुक्ति और पुनर्वास के लिए पूरा प्रयास करते हैं। जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी, मंत्री महोदय, ने कहा है, हम चाहते हैं कि इस देश में बंधुआ प्रथा जल्दी से जल्दी समाप्त हो।

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : Prof. Ranga Ji is complimenting both the Ministers for doing very well.

SHRI DHARMAVIR : Thank You.

14.18 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need for improving the telephone facilies in U. P., especially in the hilly areas.

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, देश भर में उत्तर प्रदेश परिमंडल देश के उन परिमंडलों में से एक हैं, जहां प्रत्येक हजार व्यक्तियों में सबसे कम व्यक्ति टेलीफोन सुविधा का उपभोग करते हैं। इसका कारण इस क्षेत्र में टेलीफोन सेवा का अपर्याप्त विकास है, जिसके कारण नागरिक असुविधा के साथ वाणिज्यिक आदि क्षेत्रों में यह भाग पिछड़ गया है। छठी योजना अवधि में भी इस क्षेत्र में टेलीफोन सेवाओं के प्रसार की दिशा में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में आज भी बहुत बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय ऐसे हैं, जिन्हें माइक्रोवेव प्रणाली की बात छोड़ भी दें, यू० एच० एफ० प्रणाली से भी नहीं जोड़ा गया है। कहीं-कहीं तो पी० सी० ओ० भी नहीं है। नो डीले सेवा का लाभ भी बहुत कम स्थानों को प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में ही सब से अधिक व्यक्ति टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं।

उत्तर प्रदेश में भी पिछड़े पर्वतीय 6 जनपद संचार सेवाओं के मामलों में सबसे पिछड़े हैं। इन जनपदों के मुख्यालयों को यू० एच० एफ० प्रणाली से किसी भी मुख्य केन्द्र से अभी नहीं जोड़ा गया है। पिथौरागढ़, रानीखेत नामक स्थानों में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज वर्ष 1984-85 में स्थापित किए जाने के वादे पर भी अभी अमल प्रारम्भ नहीं हुआ है। रेडियो रीले प्रणाली जो इन क्षेत्रों के लिए अत्यधिक उपयोगी है, उसको लागू करने की दिशा में भी प्रयास नहीं हुआ है। इन क्षेत्रों के लिए छोटे विनिमय केन्द्र तथा पी० सी० ओ० खोलने में वर्तमान जनसंख्या तथा क्षेत्रफल तथा दूरी के मानकों को हटाना आवश्यक है। वार्डर एरिया में क्रैश प्रोग्राम के तहत पी० सी० ओ० खोले जाने चाहिएं।

अत: संचार मंत्री जी से आग्रह है कि इस दिशा में त्वरित प्रयत्न करने की कृपा करें।

(ii) Need for effectivee measures to Save from pest infection paddey crop in Puri district of Orissa.

SHRI BRAJAMOHAN MOHANTY (Puri) : I am on a point of clarification. After I submitted this 377 Notice, I got some more information. Shall I add this information ? Now I have got the additional information that some more areas are infected by pests. should I mention it ?

MR. CHAIRMAN Nothing more. Approved text only should be read out.

SHRI BRAJAMOHAN MOHANTY: Sir, Again, this year the winter paddy crop in Pipli Block of Puri district, Orissa has started being infested by pests and pesticide is not an answer to the problem. Last year, an assurance was given that the pesticide used is effective and it works against pest infection but experience has shown that it does not. Now the infection is spreading like anything and, I am afraid, shortly vast areas of winter paddy crop in different blocks of Puri district will be infected and damaged. This is going to be a great loss to the farmers. If immediate steps are not taken, the entire winter crop will be damaged. I, therefore, urge upon the Government to depute some officers to visit the spot and to take effective steps to counteract the pest infection. This needs very urgent attention of the Government.

(iii) Need to provide for allotment of D. D. A. flats and other residential accommodation on priority basis to migrant Government employees in Delhi and other metropolitan cities.

SHRI ERA ANBARASU (Chengalpattu) : People coming from different parts of the country working in Central Secretariat and other Ministries and Departments are facing lot of difficulties in getting even a single room at a normal rent to live in. This accommodation problem is one of the chronic problems faced by these migrants. Majority of these migrants are not having any houses of their own to live in.

Shelter is one of the primary necessities of man next to food and clothing. But a total estimated number of 25,000 migrants from the remotest parts of the country in Government services in Delhi are facing lot of difficultes for suitable accommodation.

There was a policy decision of the Government not to provide Government accommodation to the employees who are having their own accommodation in Delhi or surrounding areas but this policy was changed some time ago. I request the Hon. Minister for Works and Housing to revise that policy so as to provide residential accommodation to Central Government migrant employees who are not having their own houses in Delhi.